भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2440
13/03/2026 को उत्तरार्थ

विषय: कपास की कम पैदावार और कॉट-एली प्लेटफॉर्म पर कपास उत्पादक किसानों का पंजीकरण

2440. श्रीमती सागरिका घोषः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में कपास की वर्तमान प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी है तथा इसकी अन्य प्रमुख कपास-उत्पादक देशों की पैदावार से किस प्रकार तुलना की जाती है;

(ख) क्या भारत में कपास की पैदावार तुलनात्मक रूप से कम है, यदि हां, तो इतनी कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन-से हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बीटी-कपास बीज पैकेटों के लिए निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) कॉट-एली प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए पात्र कपास उत्पादक किसानों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) अब तक इस प्लेटफॉर्म पर वास्तव में कितने पात्र किसानों ने पंजीकरण कराया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में कपास की उपज 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) के अनुसार, वैश्विक कपास उत्पादकता (2024) 834 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों जैसे चीन (2125 किलोग्राम लिंट/हेक्टेयर), ब्राजील (1845 किलोग्राम लिंट/हेक्टेयर) और अमेरिका (888 किलोग्राम लिंट/हेक्टेयर) में उपज का स्तर भारत की तुलना में अधिक है।

भारत में 67% क्षेत्र वर्षा सिंचित क्षेत्र है, जहां मौसम की चरम घटनाओं, विशेष रूप से वर्षा की कमी/अधिकता और बेमौसम बारिश की समस्या बढ़ती जा रही है। बीटी कपास में उपलब्ध क्राय (सीआरवाई) प्रोटीन में गुलाबी बॉलवर्म के प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने के कारण भारत में कपास की उत्पादकता में भी गिरावट आई है, जिससे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में इसका व्यापक प्रकोप फैल गया है। कपास की लगातार एक ही फसल की खेती ने सॉइल हेल्थ को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) में व्हाइटफ्लाई का प्रकोप और कॉटन लीफ कर्ल वायरस जैसे गंभीर कीट और रोगों के प्रकोप के साथ-साथ मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बॉल रॉट और टोबैको स्ट्रीक वायरस के कारण उपज में काफी कमी आई है। कपास स्टैम वीविल और टी मॉस्किटो बग जैसे सैकंडरी कीटों के उभरने से समस्या और बढ़ गई है। अन्य कारकों में फसल की कम कटाई सूचकांक और कम जिनिंग उत्पादन वाले लंबे समय तक चलने वाले हाईब्रिड की खेती, मिलावटी और कम गुणवत्ता वाले बीजों की उपस्थिति और अनियमित बीटी कार्यक्रमों के अंतर्गत बढ़ते क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बुआई की चरम समय में सीमित सिंचाई, उथली और संकुचित मिट्टी, फसलों के बीच अधिक स्पेस और किसानों द्वारा वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने से कपास उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। साथ ही, कपास की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर द्वारा एनएफएसएनएम के अंतर्गत 2023-24 से प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में 'एग्रो-एकोलॉजिकल जोनों के लिए लक्षित प्रौद्योगिकियां - कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' शीर्षक से एक विशेष कपास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण, 2025 में "कपास उत्पादकता मिशन" की घोषणा की है। इस पंचवर्षीय मिशन का उद्देश्य कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाना और अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना है।

(ग): वर्ष 2022 से 2025 के दौरान बीटी-कपास के बीज के पैकेटों के लिए निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बीटी-कॉटन का मूल्य प्रति 450 ग्राम पैकेट (धनराशि रुपये में)	
	बीजी-I	**बीजी-II**
2022	635	810
2023	635	853
2024	635	864
2025	635	901

(घ) एवं (ङ): कॉट-एली मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस प्लेटफॉर्म पर कपास किसानों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नौ क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उपलब्ध था। इस एप्लिकेशन का उद्देश्य कपास किसानों को किस्मवार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन के अंतर्गत आने वाले निकटतम खरीद केंद्रों के बारे में सूचित और अद्यतन रखना और भुगतान की स्थिति जानने तथा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) से सीधे संवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। हालांकि, यह एप्लिकेशन एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अंतर्गत कपास की बिक्री के लिए कपास किसानों के पंजीकरण हेतु नहीं था। इस उद्देश्य के लिए, 1 सितंबर 2025 से कपास किसानों को सशक्त बनाने हेतु सीसीआई द्वारा एक नया मोबाइल एप्लिकेशन, कपास किसान, लॉन्च किया गया है। एमएसपी प्रचालनों के अंतर्गत, किसानों द्वारा कपास की बिक्री केवल इसी एप्लिकेशन के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है। इस ऐप के माध्यम से, किसान स्व-पंजीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, यह सुविधा चार सप्ताह के अंतराल पर उपलब्ध है, जिससे किसानों को अधिक लचीलापन मिलता है, प्रतीक्षा समय कम होता है और खरीद केंद्रों पर भीड़-भाड़ से बचा जा सकता है। तद्नुसार, सीसीआई कपास की खरीद केवल कपास किसान ऐप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग द्वारा ही कर रहा है। अब तक लगभग 42 लाख कपास किसानों का पंजीकरण कपास किसान मोबाइल ऐप पर हो चुका है।

******